महत्वपूर्ण एवं खास

पिछले 24 घंटों में 429 लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव, 72 घंटों में नहीं मिला कोई संक्रमित

कोरबा (आरएनएस)। कोरोना संक्रमण की जांच से जुड़ी राहत भरी खबर कोरबा जिले के लिए है। पिछले 72 घंटों में कोरबा जिले से भेजा गया कोई भी सेम्पल जांच में पाजिटिव नहीं आया है। पिछले 24 घंटों में हुई जांच में कोरबा जिले के 429 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव मिली है इसे मिलाकर जिले में अब तक एक हजार 867 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए, जिले से भेजे गये एक हजार 953 सेम्पलों में से अब तक एक हजार 895 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। केवल 28 लोग ही अब तक इस जांच में संक्रमित पाये गये हैं। अभी भी जिले से भेजे गये 58 नमूनों की कोरोना जांच रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक कोरबा जिले के 17 मरीज कोरोना मुक्त होकर वापस लौट आये हैं। जिनमें से एक कोरबा शहर और बाकी 16 कटघोरा के हैं। रायपुर एम्स में वर्तमान में कटघोरा के 11 कोरोना संक्रमितों का ईलाज चल रहा है।

प्रेशर आईडी की चपेट में आने से सुअर की हुई मौत

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के ग्राम श्यामगिरी से टिकनपाल जाने वाली कच्ची सड़क पर नक्सलियों ने प्रेशर आईडी लगा रखा था, जिसकी चपेट में आकर एक सुअर की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने प्रेशर बम जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया था। लेकिन इसके चपेट में सूअर के आ जाने से नक्सलियो के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। जब देश एकजुट होकर कोरोना से लड़ रहा है उस वक्त नक्सली अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं।

नक्सलियों ने की बुजुर्ग की हत्या

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के थाना कटेकल्याण के ग्राम मारजूम भीमापारा में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी क्रूरता का प्रर्दशन करते हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग जगरा राम मंडावी की निर्ममता पूर्वक पूरे गांव के सामने डंडों से पीट-पीटकर तड़पाकर, उसके बाद गले में फंदा डालकर हत्या कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक बुजुर्ग जगरा राम मंडावी गोपनीय सैनिक दुलगा मंडावी के पिता थे, नक्सलियों ने गोपनीय सैनिक का बदला उसके पिता को पूरे गांव के सामने पहले तो डंडों से पीट-पीटकर तड़पाया उसके बाद गले में फंदा डालकर फांसी में लटकाकर विभत्स तरीके से हत्या को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने इस कृत्य को पूरे गांव के सामने अंजाम दिया है। एक बुजुर्ग के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना नक्सलियों की विक्रित मानसिकता को दर्शाता है। अपने वजूद को बनाये रखने के लिए दहशत का तथाकथित नक्सलवाद के तालीबानी सत्ता का भौडा प्रर्दशन से इनकी वास्तविकता उजागर हो रही है। उल्लेखनिय है कि नक्सलियों ने जगरा राम मंडावी की हत्या 17 अप्रेल की रात्रि 08 बजे कर दिया था। मृतक के परिजनों ने नक्सलियों के भय से मृतक का शव बिना पुलिस में रिपोर्ट लिखाये दफना दिया, लेकिन जैसे ही कटेकल्याण पुलिस को मामले की जानकारी मिली हुई पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्जकर जांच के साथ ही एसडीएम से अनुमति लेकर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

वन क्षेत्रपाल कन्नौजे निलंबित

रायपुर (आरएनएस)। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी द्वारा वन मंडल गरियाबंद के अंतर्गत इन्दागांव के परिक्षेत्र अधिकारी, वन क्षेत्रपाल महादेव कन्नौजे को वित्तीय अनियमितता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वन क्षेत्रपाल कन्नौजे का मुख्यालय रायपुर वृत्त कार्यालय, रायपुर निर्धारित किया गया है। वन क्षेत्रपाल कन्नौजे द्वारा इन्दागांव परिक्षेत्र के माहुलकोट परिसर में वृक्षारोपण तथा सुरक्षा कार्य और घुमरगुड़ा तथा धुपकोट परिसर में सुरक्षा कार्य तथा अग्नि सुरक्षा कार्य आदि में वित्तीय अनियमितता होना पाया गया है।

छत्तीसगढ़ में सभी के लिए खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था : खाद्य मंत्री भगत

» बिना राशनकार्ड वाले व्यक्तियों को भी 5 किलो चावल

» अनुसूचित व माडा क्षेत्र के सभी राशनकार्डधारियों को एक किलो निःशुल्क चना

» लॉकडाउन की अवधि में बनाए गए 30 हजार नए राशनकार्ड

» परिवार के छूटे हुए 44 हजार लोगों के राशनकार्डों में जोड़े गए नाम

» खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी

» लॉकडाउन में अभूतपूर्व सहयोग के लिए नागरिकों को दिया धन्यवाद

रायपुर (आरएनएस)। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा की। भगत ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए किए गए लाकडाउन के दौरान प्रदेश में सभी परिवारों के लिए समुचित खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों पर अब बिना राशनकार्ड वाले व्यक्तियों को भी प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया जा रहा है। भगत ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लगभग 30 हजार परिवारों के नए राशनकार्ड बनाए गए हैं। साथ ही 44 हजार से अधिक छूटे हुए व्यक्तियों का नाम राशनकार्डों में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के हर संभव प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। भगत ने लाकडाउन के दौरान प्रदेश की जनता से प्रशासन को मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद भी दिया। भगत ने कहा कि राज्य शासन ने इस महामारी से निपटने के लिए हर क्षेत्र में कुशल प्रबंधन किए हैं और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में कोरोना का प्रकोप काफी कम व नियंत्रित है। कोरोना वायरस से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को राज्य सरकार ने काफी पहले भांपकर लॉकडाउन के पहले से ही इसके लिए गंभीर प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। इन विषम परिस्थितियों में खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी लोगों के लिए समुचित खाद्यान्न की व्यस्था की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में राज्य के हितग्राहियों को खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता में कोई कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा व निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्डधारी परिवारों को 3 माह अप्रैल, मई व जून 2020 का चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्णय का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए खाद्य विभाग ने लॉकडाउन के पहले ही 22 मार्च से 02 माह, अप्रैल व मई, 2020 का खाद्यान्न एकमुश्त आबंटित करते हुए इसका भण्डारण शुरू कर दिया था। 30 मार्च तक 90 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों में एवं 05 अप्रैल तक राज्य के शत-प्रतिशत 12 हजार 306 उचित मूल्य दुकानों में 02 माह का खाद्यान्न भण्डारण पूर्ण करा लिया गया। लॉकडाउन की विशम परिस्थितियों में जहां एक ओर हमालों एवं परिवहन की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती रही। राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन लगभग 1200 वाहनों के माध्यम से भण्डारण की व्यवस्था पूर्ण की गयी। राज्य में अब तक 65.63 लाख राशनकार्डधारियों में से 57.87 लाख राशनकार्डधारियों को दो माह का खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। राज्य में विभिन्न श्रेणी के राशनकार्डधारियों द्वारा अब तक लगभग 3 लाख 64हजार 793 टन चावल, 9,654 टन शक्कर, 10,351 टन नमक, 2,548 टन चना एवं 979 टन गुड़ का उठाव किया जा चुका है।हितग्राहियों को प्रदान की जा रही 03 माह की राशन सामग्री पर राज्य शासन द्वारा कुल 3,328.55 करोड़ रूपए खर्च किया गया हैं। इसमें 3 माह के लिए प्रदान किये जा रहे अतिरिक्त चावल पर लगभग 950 करोड़ रूपये की अनुमानित सब्सिडी राशि शामिल है। राज्य शासन द्वारा भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अतिरिक्त पात्रता के बराबर ही राज्य योजना के सभी राशनकार्डों में अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदाय किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा लगभग 8.96 लाख सामान्य (एपीएल) राशनकार्डधारियों को भी निर्धारित पात्रतानुसार 10 रूपए प्रति किलो की रियायती दर पर चावल वितरित किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा अब तक राज्य के 85 अनुसूचित विकासखण्डों व 9 माडा क्षेत्रों के अंत्योदय व प्राथमिकता श्रेणी के लगभग 25 लाख राशनकार्डधारियों को ही 5 रूपए प्रति किलो की उपभोक्ता दर पर 2 किलोग्राम चने का प्रतिमाह वितरण किया जा रहा था।

महिलाओं ने पकड़ी दारू, गटक गया कोटवार

» सांकरा में रक्षक ही बना भक्षक

गरियाबंद (आरएनएस)। लॉक डाउन के दौरान अवैध शराब सप्लाई और खपत की कई तरह की शिकायत आ रही हैं। इस बीच ग्राम सांकरा में नया तरह का मामला सामने आया है। जहां महिलाओं द्वारा पकड़ी गई शराब को गांव का कोटवार ही गटक गया। इसमें भी दिलचस्प है कि कोटवार शराब सप्लायर को छोड़ने की बात सहजता से स्वीकार कर रहा हैं। वहीं कुछ लोगो का आरोप है कि कोटवार ने शराब सप्लायर से लेनदेन कर उसे छोड़ा है।

लॉक डाउन में सरकारी शराब दुकानें बंद होने के कारण अंचल के गांवों में महुआ शराब की अवैध सप्लाई और बिक्री बढ़ गई है।ऐसा ही मामला पाण्डुका थाना क्षेत्र के ग्राम सांकरा में सामने आया है। जहां शुक्रवार को शाम करीब साढ़े पांच बजे दीवना तौरेंगा की ओर से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में आ रहा था। उसी समय गांव की पुलिस सखी में शामिल महिलाएं बाहर से आने-जाने वाले व्यक्तियों की जांच कर रही थी। उक्त मोटर साइकिल सवार की जांच की गई तो डिक्की में पांच लीटर से अधिक महुआ शराब रखा हुआ था। जिसे पकड़कर गांव के कोटवार घनाराम नागरची के हवाले किया गया। महिलाओं का कहना है कि कोटवार ने उक्त व्यक्ति और महुआ शराब को पुलिस के हवाले करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे अंदेशा है कि कोटवार लेनदेन कर खुद शराब को गटक गया होगा। कोटवार भी शराब सप्लाई करने वाले व्यक्ति को महिलाओं द्वारा खुद के हवाले करने की बात स्वीकार रहा है। उनका कहना है कि शराब सप्लायर ने काफी मिन्नतें मांगी, इसके चलते उसे छोड़ दिया गया।

गौठानों में सब्जियों की खेती से स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने कमाए 74 हजार

» मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं गौठान

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने देशव्यापी लॉक-डाउन के दौरान जब रोजगार की अधिकांश गतिविधियां ठप्प हैं, तब ऐसे समय में कांकेर जिले के स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने गौठानों में सब्जियों की खेती कर 74 हजार 600 रूपए कमाए हैं। जिले के 17 गौठानों में 34 स्वसहायता समूह सब्जी उत्पादन कर रही हैं। लॉक-डाउन के दौर में ये महिलाएं अपने गांव के साथ ही आसपास के गांवों में भिण्डी, बरबट्टी, मिर्ची और कई प्रकार की भाजियों की आपूर्ति कर रही हैं। सब्जियों की बिक्री से नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम गुहान की जय मां लक्ष्मी स्वसहायता समूह को 12 हजार 400 रूपए और चारामा विकासखण्ड के मरकाटोला की ज्योति स्वसहायता समूह को नौ हजार 500 रूपए की आमदनी हुई है।

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे गौठान पशुधन के संरक्षण-संवर्धन के साथ ही रोजगार का भी केंद्र बन रहे हैं। इन्हें स्थानीय ग्रामीणों के रोजगार के लिए मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूह की महिलाएं गौठानों और चारागाहों के लिए आरक्षित अतिरिक्त भूमि पर सब्जी उत्पादन के साथ ही मक्का उत्पादन, सीमेन्ट पोल निर्माण, मछली पालन और मशरूम उत्पादन कर कमाई कर रही हैं। इससे गांव में ही अनेक महिलाओं को स्थायी रोजगार मिल रहा है। गौठानों में कंपोस्ट खाद बनाने और फल-फूल व सब्जियों के उत्पादन के लिए बाड़ी विकास की भी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

बीमार बुजुर्गों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं सहित हाई रिस्क वाले सभी लोगों को क्वारेंटाईन करने की मुहिम

» कोरोना के फैलाव को रोकने की कवायद

» कलेक्टर कौशल ने कटघोरा में की अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, दिये जरूरी निर्देश

कोरबा (आरएनएस)। कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुके कटघोरा के वार्ड नंबर 10 एवं 11 से संक्रमण के लिए हाई रिस्क संभावना वाले सभी लोगों को क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित क्वारेंटाईन सेंटरों में रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में आज कलेक्टर किरण कौशल ने स्थानीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने तथा इसे नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कौशल ने कोरोना संक्रमित कोर एरिया पुरानी बस्ती जामा मस्जिद पारा से सभी गर्भवती महिलाओं, शून्य से छह माह तक के बच्चों वाली शिशुवती माताओं सहित सभी बुजुर्गों को भी सुरक्षित क्वारेंटाईन सेंटरों में रखने के निर्देश दिये। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, किडनी के रोग आदि से पीड़ित बीमार बुजुर्गों को भी संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए तत्काल कोर एरिया से बाहर क्वारेंटाईन सेंटरों में शिफ्ट करने के निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिये। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ एस. जयवर्धन, एसडीएम सूर्यकिरण तिवारी, सीएमएचओ डा. बी.बी.बोडे, डीपीएम पद्माकर शिंदे भी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि तत्काल सर्वेलेंस टीम द्वारा कोर एरिया का घर-घर सर्वे कर बीमार बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं की पतासाजी की जाये और सूची तैयार कर उन्हें अलग-अलग सुरक्षित क्वारेंटाईन सेंटरों में भेजने की व्यवस्था की जाये। कलेक्टर ने आगामी एक-दो दिन बाद कोर एरिया के सभी घरों को भीतर से सोडियम हाइपोक्लोराईड सल्यूशन छिड़काव कर विसंक्रमिकृत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पूरे कटघोरा शहर को भी लगातार सेनेटाईज करते रहने के निर्देश दिए।

होम डिलेवरी में अब सब्जियां भी शामिल, घर बैठे मंगा सकेंगे कोरोना प्रभावित लोग- बैठक में कलेक्टर कौशल ने अति आवश्यक सेवाओं में दवाई, राशन के साथ-साथ अब सब्जियों को भी शामिल कर दिया है। कोरोना प्रभावित कटघोरा के लोगों को अब सब्जियां दवाई और राशन की तरह वाट्सएप्प ग्रुप पर आर्डर करने से घर बैठे मिल जायेगी।

समर्थन मूल्य के अंतर की राशि बजट में 1 अप्रैल से किसानों के खाते में देने की घोषणा,मात्र घोषणा रह गई-मोर्चा

रायपुर (आरएनएस)। राज्य आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश नेता अनिल दुबे, ,लालाराम वर्मा,अशोक ताम्रकार, चेतन देवांगन, महेंद्र कौशिक,ईश्वर साहू, गोवर्धन वर्मा,गिरधारी ठाकुर, चंद्रप्रकाश साहू केशरी जैन,परसराम ध्रुव, लुकेश्वर सेन, अशोक कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर 2500/-रुपये प्रति क्विं. धान की खरीदी का वादा पूरा करने के लिए 1835/-रुपये से बची अंतर की राशि 665/-रुपये हिसाब से किसानों के खाते में देने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने 01 अप्रैल से देने की विधानसभा में घोषणा की थी।कोविड - 19 के कारण सत्ताधारी दल ने समर्थन मूल्य के अंतर की राशि आज दिनांक तक किसानों के खाते में नहीं पहुंचाया है और महामारी का नाम लेकर लगभग 01माह बीता दिया जा रहा है। किसान अधर में हैं। सत्ताधारी दल सुध नहीं ले रहा है।किसी भी कीमत में 01 पखवाड़े के अंदर भुगतान करने की मांग किसान मोर्चा ने सरकार से की है।

राज्य में रोजाना 2 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को मिल रहा निःशुल्क भोजन व खाद्यान्न

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप राज्य के सभी जिलों में गरीबों, अन्य स्थानों के श्रमिकों एवं निराश्रित लोगों को निःशुल्क भोजन व खाद्यान्न पैकेट उपलब्ध कराए जाने का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ राज्य में रोजाना दो लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन एवं खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित राहत शिविरों में रह रहें अन्य प्रदेशों के प्रवासी श्रमिकों सहित छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद लोगों को चाय, नाश्ता, भोजन एवं अन्य आवश्यक सामग्री जिला प्रशासन एवं समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से निःशुल्क प्रदाय की जा रही है। आज 19 अप्रैल को राज्य में दो लाख 16 हजार 90 लोगों को एक ओर जहां निःशुल्क भोजन एवं खाद्यान्न सामग्री प्रदान की गई वहीं दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए 72 हजार 521 मास्क एवं सेनेटाइजर का निःशुल्क वितरण किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के चलते जिलों में प्रशासन द्वारा समाजसेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं के सहयोग से संचालित राहत कार्यक्रमों एवं शिविरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 35 लाख 70 हजार 668 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं खाद्यान्न पैकेट उपलब्ध कराया गया है। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए राज्य में अब तक 32 लाख 73 हजार 362 मास्क,

गाँव मे जंगली जानवर का आतंक बेजुबान मवेशी हो रहे शिकार

गरियाबंद (आरएनएस)। ग्राम पंचायत खरता के आश्रित ग्राम आमागांव में पिछले एक सप्ताह पहले से तेंदुआ ग्राम के आसपास में अपना डेरा जमा कर मावेशियो का शिकार कर रहा हैं । ग्रामीणो से जानकारी लेने पहुंचने पर बताये की ग्राम में शाम होते ही गांव से आसपास दो तेंदुआ आ जाता है जो जोड़े मे शिकार करता है अब तक लगभग बीते 15 दिनों के अंदर चार गाय और एक भैस को आपना शिकार बना चुका है । तीन रोज पहले ग्रामीण कन्हैया लाल गोंड पिता बिसाहु गोंड का एक बछडे को दो तेंदुआ द्वारा अपना शिकार बना लिया जिससे ग्रामीणो में भय का माहौल बना हुवा है ज़ब गांव वालो को पूछा गया की क्या वन विभाग को इस बारे मे अवगत कराया गया तो ग्रामीणो ने बताया की बहुंत हाथ पाव मारने के बाद मुआवजा

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्ड एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षेत्र में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल विरोह पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्यों में फंसे एक लाख 85 हजार से अधिक श्रमिकों के समस्याओं का हुआ समाधान

» अन्य राज्यो में फंसे 81 हजार 711 श्रमिको को पहुँचाई गई राहत

» 7 हजार 384 श्रमिकों के खाते में 24.31 लाख रूपए किया जमा

» भूटान में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को दिलायी गई राहत

रायपुर (आरएनएस)। लॉकडाउन से प्रभावित छत्तीसगढ़ प्रदेश तथा देश के अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य सरकार ने 18 अप्रैल तक संकटग्रस्त एक लाख 85 हजार से अधिक श्रमिकों के समस्यायों का त्वरित समाधान किया गया। छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्यो में फंसे 81 हजार 711 श्रमिको को राहत पहुंचायी गयी। अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों में से सात हजार 384 श्रमिकों के खाते में तत्कालिक व्यवस्था के लिए लगभग 24 लाख 31 हजार रूपए भी जमा करवाया गया है। छत्तीसगढ़ के श्रमिक 21 अन्य राज्यों एवं चार केन्द्र शासित प्रदेशों में संकट की स्थिति में होने के संबंध में जानकारी मिली है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायगढ़ के श्रमिक रोहित सिंह के भूटान में फंसे होने की जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन एवं नियोजक से समन्वय कर उनके वेतन, रहने-खाने की व्यवस्था करायी गई है। इसी तरह उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में मुंगेली जिले के मजदूर कमल साहू का मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को तत्काल राज्य शासन द्वारा सहायता राशि 1.05 लाख रुपये प्रदान की गई, वंही संबंधित नियोजक द्वारा भी क्षतिपूर्ति के रूप 2.20 लाख रुपये दिलवाई गई। इसके अलावा इन श्रमिकों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जिला बेमेतरा के 3553 श्रमिक, मुंगेली जिले के 3432 श्रमिक, कबीरधाम के 2724 श्रमिक, दुर्ग के 58 श्रमिक, रायगढ़ के 30 श्रमिक, सूरजपुर के 29 श्रमिक, गरियाबंद के पांच श्रमिक, कोरबा के दो श्रमिक और बलरामपुर के एक श्रमिक के खातें में इस तरह कुल सात हजार 384 श्रमिकों के खातों में 24 लाख 31 हजार रुपये जमा कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों का दल गठित कर सतत् निगरानी की जा रही है।

इसके लिए श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाईन नम्बर 0771-2443809, 91098-49992, 75878-22800 सहित जिला स्तर पर भी हेल्पलाईन नम्बर स्थापित किए गए हैं। हेल्पलाईन नम्बर के माध्यम से प्राप्त श्रमिकों की समस्याओं को पंजीबद्ध कर तत्काल यथासंभव समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर श्रम विभाग के सचिव सोनमणी बोरा के मार्गदर्शन में अन्य प्रदेशों के स्थानीय प्रशासन से सतत् समन्वय कर श्रमिकों की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जा रहा है।